About the projects which you have asked me, I will have to make enquiries.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी मंत्री जी ने अपने उत्तर में इन्क्रोचमेंट हटाने के लिए क्या कार्य योजना है इसका जिक्र किया है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने इन्क्रोचमेंट हटा दिए गये हैं ।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि दिल्ली में विशेष रूप से साऊथ दिल्ली में कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल पर अतिक्रमण झुग्गी-झोपड़ी वालियों का है ए भाग और (बी) क्या सरकार के पास ऐसी कोई वैकल्पिक योजना है कि इन झुग्गी-झोपड़ी वासियों को उनकी बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने के बाद उनको अन्य स्थानों पर व्यवस्थापित कर दिया जाएगा ?

क्या मंत्रालय ने इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाई है यदि बनाई है तो उसका विवरण क्या है ? उसका पालन कब तक हो जाएगा और कितने झुग्गी-झोपड़ी वासियों को किन नियमों के तहत किन शर्तों के तहत उनका व्यवस्थापन हो जाएगा ।

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I think this question relates to the rimoval and resettlement of the people who have encroached on the land.

As I mentioned just now, there is a policy pertaining to this. If there is a squatter or encroachment is done on a land it can only be cleared, if the owner of that land gives about Rs. 40,000 for the resettlement of these people to another area. This is the policy.....

MR. CHAIRMAN: Which I think, they are not prepared to give.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mr. Subramanian Swamy, kindly ask your question later. You have got something else in mind.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, this is just a point of information. The Question Hour is for that.

The 'Urbane' Development Minister has just now said that encroachment is a cognizable offence and that she would welcome specific instances of encroachment so that action could be taken. Now, I would like to know whether the Minister is aware that the 'Mid-Day' of the last two days mentioned about 'The Statesman' having encroached land. Is her attention drawn to this report and if so, has she asked for a CBI inquiry or any such inquiry? The report is about the Statesman Building in Connaught Place, on Barakhamba Road. Madam, are you aware of this report at all? If not, I would be happy to give you a copy of this.

SMT. SHEILA KAUL: Please give me a copy of it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, will she take action if the report is accurate?

MR. CHAIRMAN: After she reads it.

महाराष्ट्र में किले

***243. डा० बापू कालदाते :**
श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन महाराष्ट्र में कौन-कौन से किले हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये इन किलों पर विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने अनुमति मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

†सभा में यह प्रश्न श्री विश्वासराव रामराव पाटिल द्वारा पूछा गया ।

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन महाराष्ट्र में जो किले हैं; उनकी सूची विवरण के रूप में सभा-पटल पर रखी है।

(ख) से (घ) रायगढ़ किले के विकास के संबंध में, राज्य सरकार ने निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने के लिए अनुमति मांगी है :—

(i) शिवाजी की मूर्ति के ऊपर मेघादम्बरी का निर्माण ;

(ii) चिट्टा-दरवाजा से रायगढ़ किले तक सीढ़ियों की मरम्मत ;

(iii) रायगढ़ किले पर रास्ते का निर्माण ;

(iv) रायगढ़ किले पर सफाई संबंधी सुविधाओं और विश्रामी स्थलों का निर्माण ।

मद (ii) और (iii) के लिए अनुमति पहले ही दी जा चुकी है । प्रस्तावित मेघादम्बरी (सजावटी शैड) के निर्माण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह पर्यावरण के अनुकूल मेल मिलाने के लिए डिजाइन को संशोधित करे । जहां तक सफाई संबंधी सुविधाओं और विश्रामी स्थलों की व्यवस्था किए जाने का संबंध है, इन्हें सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है ; किन्तु, साथ ही, यह सुझाव दिया गया है कि ये ढांचे पर्यावरण से मेल खाने चाहिए।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन किलों की सूची

क्र० सं०	स्थान	किले का नाम
1	2	3
1.	बालापुर	बालापुर किला
2.	नारनाला	किला
3.	चिकाल्दा	गाविलगढ़ किला
4.	दौलताबाद	दौलताबाद किला
5.	परतापगढ़	किला
6.	पौनी	पौनी किला
7.	सायन	सायन का पहाड़ी किला
8.	बल्लारपुर	किला
9.	भांडक	किला
10.	चन्दा	किला
11.	मुरमगांव	टीपागढ़ की गढ़ी
12.	वैराबढ़	किला
13.	अलीबाग	हीराकोटे पुराना किला
14.	अलीबाग	कोलाबा किला
15.	बीरवाड़ी	बीरवाड़ी किला
16.	घेरासुरगढ़	घेरा गढ़ या सुरगढ़ किला
17.	घोसले	घोसलगढ़ किला
18.	मन्जसारी कंशोरी	पुराना किला
19.	कोरलै	पुराना किला
20.	सुरूड	कासा किला
21.	पेठ	कोटली किला
22.	राजपुरी	जंजीरा किला
23.	रायगढ़	रायगढ़ का किला
24.	ताला	ताला किला
25.	पन्हाला	पन्हाला किला
26.	भाधागढ़	पहाड़ी पर पुराने किले के अवशेष

1	2	3
27.	डोंगरताल	किला
28.	जुन्नार	शिवनेरी का किला
29.	लोहागढ़	किला
30.	राजमाची	किला
31.	वीसापुर	किला
32.	हरनै	सुवर्णदुर्ग किला
33.	जयगढ़	जयगढ़ किला
34.	मलवान	सिन्धु दुर्ग किला
35.	विजयदुर्ग	विजयदुर्ग किला
36.	मचनूर	औरंगजेब का किला
37.	शोलापुर	पुराना किला
38.	अरनाला	किला
39.	बेसिन	किला
40.	माहूली	माहुली किला
41	पवनार	किला

MR. CHAIRMAN: The Minister is answering a parliamentary question for the first time.

AN HON. MEMBER: Maiden reply.

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : सभापति महोदय, रायगढ़ जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी तो यह रायगढ़ पर जो व्यवस्था, सुविधाएं करने के लिए अनुमति मांगी गई थी वह महाराष्ट्र सरकार ने दे दी है । उसके अलावा वहां कहीं आर्गेनाइजेशन ने और वहां पुणे के एक कांट्रैक्टर ने रायगढ़ पर रोप-वे निर्माण करने की योजना अब बन रही है । उसके लिए वहां डायनामाइट से वह खम्भे वहां जो वहां के मैनुयस जिसको बोलते हैं मेना दरवाजा, मेना गेट जो है तो उस पर वह खंभे डायनामाइट से कर रहे हैं । इस डायनामाइट की वजह से वहां जो पुराने 300 वर्ष के स्मारक हैं वहां शिवाजी का महल है, वहां एक स्तम्भ है और दूसरे कोई वहां नगाड़खाना है वह तो क्षतिग्रस्त है ही, लेकिन यह डायनामाइट की वजह से यह पुराने नष्ट होने का बहुत ही आशंका है और इसके लिए दूसरा एक बात है कि वह गंगासागर तालाब है बड़ा छत्रपति के समय का वह गंगासागर के तालाब का पानी इससे नष्ट होने की आशंका है इस डायनामाइट की वजह से और पुरातत्व विभाग जो है उन्होंने उसको देख-रेख के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की है और बुरी तरह से वह डायनामाइट वहां से चला रहे हैं इसका कोई जिक्र आप मिनिस्टर करेंगी या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

कुमारी शैलजा : सर, जहां तक रोप-वे का सवाल है वह ए०एस०आई० प्रोटैक्टेड मोनूमेंटस है उसके बाहर है तो उसके लिए तो परमिशन दी गई है, लेकिन जहां तक डायनामाइट की बात है कि डायनामाइट यूज़ किया जा रहा है उसको हम वेरीफाई करेंगे और अगर उससे कोई स्पोयल होता है, खराब होता है तो जरूर उसको रोक दिया जाएगा ।

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : इसमें दूसरा यह है कि यह रोप-वे के बाद यही आर्गेनाइजेशन वहां एक मिनी रेल, रायगढ़ दिखाने के लिए मिनी रेल की आयोजना करने वाली है उनकी भी अनुमति मांगी है, मुझे नहीं मालूम कि वह अनुमति दी है या नहीं । वैसे अगर रेल बनायी गयी तो रायगढ़ का सारा ऐतिहासिक सौंदर्य नष्ट हो जायेगा और वहां बम्बई की चौपाटी बन जायेगी और लोग यह भूल जायेंगे कि वहां छत्रपति रहते थे । इसलिये जिनको रायगढ़ देखना हो तो वह खुद पैदल चलकर देख सकते है । यह नहीं कि वहां वे कार में घूमे या वहां रेल चले और वहां का ऐतिहासिक सौंदर्य खराब हो जाये ।

सभापति जी, दूसरी बात यह है कि इस प्रश्न के तहत हमने पूछा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कौन-कौन किले हैं ? उसके जवाब में इसमें एक लिस्ट दी गयी है, लेकिन उसमें बहुत सारे किलों के नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे वहां सिंहगढ़

पुणे के पास, उसका नाम नहीं है। राजगढ़ है, कोलापुर डिस्ट्रिक्ट में भुदरगढ़ है, वसई का एक जंजीरा किला है और एक पावनगढ़ है पनाला के नजदीक। ये सभी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही मत्हवपूर्ण किले हैं, लेकिन उनका जिक्र इस लिस्ट में नहीं हैं और इनका होना बहुत जरूरी है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इनका एडीसन हो जायेगा या नहीं ?

KUMARI SELJA: Sir, as far as mini-rail is concerned, we have not given permission for that so far. And the second part of his question is about the forts which are not mentioned in the list. In this respect, I would like to inform the hon. Member that only the Centrally protected monuments are mentioned in the list and not others.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Sir, out of the list of 41 forts, Balapur fort, Narnala fort, Pauni fort, Bhandak fort and Chanda fort, are in a highly dilapidated condition. Out of these forts, the Narnala fort in Bhuldana district which place the hon. Deputy Minister had toured, I think, last month, is in a very bad state. The local P.W.D. has offered to conduct the repairs. Will the Government give permission to the local P.W.D. to do the same? The ASI is not carrying out the necessary repairs. If the local P.W.D. comes forward, will the Government give permission? This is part (a) of my supplementary. Part (b) of my supplementary is, eight months ago; Sir; you nominated us to the Central Advisory Board of Archaeology and for the last eight months, no meeting is held. Will that meeting be held soon so that we can tell them that these forts are in bad conditions?

KUMARI SELJA: Well, the meeting will be held soon. As far as Narnala fort is concerned, since the hon. Member has mentioned that, I would like to inform him that we have proposed to spend about 70,000 rupees in the year 1993-94 for the maintenance and repair work. If this amount is not enought, we are prepared to spend more.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: What about the meeting of the Central Advisory Board of Archaeology?

MR. CHAIRMAN: She said that it will be held soon.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, in the list of 41 forts, Daulatabad fort is at serial number 4. This fort is situated near Ajanta and Ellora and there is a plan of the Central Government to develop a tourist centre around Ajanta and Ellora with the aid of Japan. They are spending about 200 crores of rupees on that project. The Daulatabad fort is even older than Raygad, Rajgarh and Partabgarh forts. Will the development of Daulatabad fort be also included in the Ajanta-Ellora development project which is being taken up with the aid of Japan?

Secondly, as my friend has rightly pointed out, there are so many forts which are not incuded in this list. I come from disriet Nanded. There are two forts. You can verify this fact from the hon. Home Minister because he also comes from the same area. The name of one fort is Mahur. There is a big Renuka Devi temple there and people from far and wide go there and have *darshan*. There is a big fort known as Mahurgarh there. Another fort is Kandhar in ditsriet Nanded. These two forts have not been included in this list. May I request the hon. Minister whether these two forts will be included in the list and some survey will be done and proper development of these forts will take place and all efforts will be put to retain their past glory at any cost? I would like to know these things from the Minister.

KUMARI SELJA: Sir, as regards the first part of his question, the Daulatabad Fort is included in the Ajanta-Ellora Development Scheme which is being done with the help of the

Japanese. As far as our own sources are concerned, we spent about Rs. 61,000 last year, i.e., 1992-93, and if needed, we are prepared to spend more.

Sir, the inclusion of these monuments is left to the Archaeological Survey of India, and if it is considered to be a monument of national importance, then the Archaeological Survey of India can take it; otherwise, the State Government can also protect it.

केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान

*244. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का संचालन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान की स्थापना कब की गयी थी तथा गत तीन वर्षों के दौरान बजट आबंटन में से इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान पर व्यय की गई कुल राशि में से अनुसंधान कार्य पर कितने प्रतिशत राशि व्यय की गयी है ;

(घ) इस संस्थान द्वारा वर्ष 1990 से सफलतापूर्वक किये गये उन नये शोध कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनसे उत्पादकों को उत्पादन दर बढ़ाने में सहायता मिली है ;

(ङ) क्या सरकार ने इन नयी तकनीकों तथा शोध कार्यों का लाभ उत्पादकों तक पहुंचाने के लिये कोई कार्य-योजना बनायी है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है

*सभा में यह प्रश्न डा० जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा पूछा गया ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTION ENERGY RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Sir, the Institute is under the administrative control of Indian Council of Agricultural Research.

(b) The Institute was established in January 1924 by erstwhile Indian Central Cotton Committee in the name of Cotton Technological Research Laboratory. After the abolition of ICCC, it came under the direct administrative control of Indian Council of Agricultural Research with effect from April 1, 1966. The Laboratory was renamed as Central Institute for Research on Cotton Technology with effect from April 1, 1991. The total amount spent on it during the last three years (1989-90 to 1991-92) has been Rs. 820.43 lakhs.

(c) About 63 per cent of the total expenditure has been spent on research work during the last three years.

(d) This institute does not undertake research work for increasing the production or productivity of cotton.

(e) and (f) Does not arise.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, the Minister has replied that the Central Institute for Research on Cotton Technology does not undertake any research on the productivity of cotton. I would like to know from the hon. Minister whether he is aware that in terms of area of land cultivation for cotton purposes India has the largest area in the world for cotton cultivation, but in terms of productivity we are number four in the world; so, whether he agrees that there is a need for undertaking research in the country for increasing the pro-